



अखंड भारत संदेश

www.akhandbharatsandesh.net

प्रयागराज से प्रकाशित

नगर संस्करण प्रयागराज

गुरुवार 30 जून 2022

विश्व निर्माण एवं मानव विकास को द्रुतगति प्रदान करने हेतु क्रियायोग आश्रम एवं अनुसंधान आश्रम की अनुपम भेंट

महाराष्ट्र में आज ही फ्लोर टेस्ट

सुप्रीम कोर्ट से उद्भव को राहत नहीं, जेल में बंद नवाब मलिक और अनिल देशमुख को वोटिंग की इजाजत

नई दिल्ली: महाराष्ट्र विधानसभा में कल फ्लोर टेस्ट होगा। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार शाम को 3 घंटे 10 मिनट तक चली सुनवाई के बाद यह फैसला दिया। शिवसेना ने फ्लोर टेस्ट के खिलाफ, जबकि शिंदे गुट और राज्यपाल के वकील ने फ्लोर टेस्ट के पक्ष में दलीलें पेश कीं। शाम 5 बजे तक 18 मिनट से 8 बजे तक 28 मिनट तक सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इधर, कोर्ट ने जेल में बंद महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक और अनिल देशमुख को भी वोटिंग में हिस्सा लेने की इजाजत दे दी। कोर्ट ने कहा कि दोनों चुने हुए विधायक हैं और उन्हें विधानसभा में वोटिंग के बाद फिर जेल ले जाया जाएगा।



दलीलें: शिवसेना की तरफ से सौनीयर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी कोर्ट में पेश हुए। वहीं, शिंदे गुट की तरफ से पेश हुए एडवोकेट नीरज किशन कौल ने पैरवी की। एडवोकेट मनिंदर सिंह कौल की दलीलों का समर्थन करने खड़े हुए। आखिर में राज्यपाल की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलीलें रखीं। शिवसेना फ्लोर टेस्ट के खिलाफ, शिंदे गुट समर्थन में: इससे पहले सिंघवी ने फ्लोर टेस्ट पर आपत्ति जताते हुए दलील दी कि 16 बागी विधायकों को 21 जून को ही अयोग्य घोषित किया जा चुका है। ऐसे में इनके वोट से बहुमत का फैसला नहीं किया जा सकता। सिंघवी ने मांग की कि या तो बहुमत का फैसला स्पीकर को करने दें या फिर फ्लोर टेस्ट टाल दें। वहीं, कौल ने कहा कि महाराष्ट्र में सरकार ही नहीं, उद्भव की पार्टी भी अल्पमत में आ चुकी है। ऐसे में हॉर्स ट्रेडिंग रोकने के लिए

फ्लोर टेस्ट पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले क्या कहा था?

महाराष्ट्र के सियासी संकट पर सोमवार को भी सुप्रीम कोर्ट में करीब 2 घंटे सुनवाई हुई थी। सुनवाई के बाद कोर्ट ने महाराष्ट्र पुलिस, केंद्र सरकार, शिवसेना और डिप्टी स्पीकर को नोटिस जारी किया। सुनवाई में कोर्ट ने शिंदे गुट को कुछ राहत दी है, जबकि फ्लोर टेस्ट की मांग पर कोर्ट ने कुछ भी कहने से इनकार किया। शिवसेना के वकील देवदत्त कामत ने फ्लोर टेस्ट का जिक्र किया था, जिस पर कोर्ट ने कहा इस पर हम कुछ नहीं कह रहे हैं। अगर, ऐसा कुछ हुआ तो आप कोर्ट आ सकते हैं। शिंदे ने 16 विधायकों को सदस्यता रद्द करने के नोटिस और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के मुद्दे को लेकर याचिका दायिल की थी।

कैबिनेट ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों के कम्प्यूटरीकरण को दी मंजूरी

नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कार्यरत 63 हजार प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के कम्प्यूटरीकरण के लिए कुल 2,516 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय को मंजूरी दी। सुचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) की दक्षता बढ़ाने तथा उनके संचालन में पारदर्शिता एवं जवाबदेही लाने और पैक्स को अपने व्यवसाय में विविधता लाने व विभिन्न गतिविधियों और सेवाएं शुरू करने की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) के कम्प्यूटरीकरण को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना में कुल 2516 करोड़ रुपये के बजट परिव्यय, जिसमें भारत सरकार की हिस्सेदारी 1528 करोड़ रुपये की होगी, के साथ पांच वर्षों की अवधि में लगभग



63,000 कार्यरत पैक्स के कम्प्यूटरीकरण का प्रस्ताव है। उन्होंने कहा कि इससे 13 करोड़ किसानों को फायदा होगा, जिनमें अधिकांश छोटे और सीमांत किसान हैं। इस परियोजना में साइबर सुरक्षा और डेटा भंडारण के साथ क्लाउड-आधारित सामान्य सॉफ्टवेयर का विकास और पैक्स को हार्डवेयर सहायता प्रदान

करना शामिल है। इससे मौजूदा रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण भी होगा। प्राथमिक कृषि सहकारी ऋण समितियां (पैक्स) देश में अल्पकालिक सहकारी ऋण (एसटीसीसी) की त्रि-स्तरीय व्यवस्था में सबसे निचले स्तर पर अपनी भूमिका निभाती हैं, जहां लगभग 13 करोड़ किसान इसके सदस्य के रूप में शामिल होते हैं और जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित होती हैं। देश में सभी संस्थाओं द्वारा दिए गए केसीसी ऋणों में पैक्स का हिस्सा 41 प्रतिशत (3.01 करोड़ किसान) है और पैक्स के माध्यम से इन केसीसी ऋणों में से 95 प्रतिशत (2.95 करोड़ किसान) छोटे व सीमांत किसानों को दिए गए हैं। अन्य दो स्तरों अर्थात राज्य सहकारी बैंकों (एसटीसीबी) और जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों (डीसीसीबी) को पहले ही नाबाई द्वारा स्वचालित कर दिया गया है और उन्हें साइबर सॉफ्टवेयर (सीबीएस) के तहत ला दिया गया है। हालांकि, अधिकांश पैक्स को अब तक कम्प्यूटरीकृत नहीं किया गया है और वे अभी भी हस्तचालित तरीके से कार्य कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप उनके संचालन में अक्षमता और भरोसे की कमी दिखाई देती है। कुछ राज्यों में, पैक्स का कहीं-कहीं और आंशिक आधार पर कम्प्यूटरीकरण किया गया है। उनके द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे।

बिहार में ओवैसी को बड़ा झटका

पटना: बिहार की सियासत से बड़ी खबर आ रही है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में बड़ी टूट हो गई है। बताया जा रहा है कि एआईएमआईएम के पांच में से चार विधायक राजद में शामिल हो गए हैं। वहीं ओवैसी की पार्टी के चारों विधायकों के राजद में शामिल होने की खबर पर बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी मुहर लगा दी है। वहीं इस घटनाक्रम से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा के अध्यक्ष विजय सिन्हा के कमरे में एआईएमआईएम के चार विधायकों के साथ पहुंचकर मुलाकात की थी। इस दौरान जो पांचवें विधायक मौजूद नहीं थे वे थे।

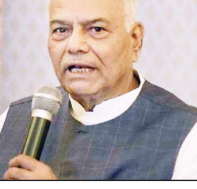
उदयपुर: भारी भीड़ के बीच कन्हैया का अंतिम संस्कार हुआ



उदयपुर: राजस्थान के उदयपुर में टेलर कन्हैयालाल का बुधवार दोपहर अंतिम संस्कार कर दिया गया। शहर में कर्फ्यू के बाद उनकी अंतिम यात्रा में भारी भीड़ जुटी। लोगों ने हत्यारों को फांसी दो... फांसी दो के नारे लगाए। पूरा शहर कन्हैया की हत्या के विरोध में बंद रहा। किसी भी हालात से निपटने के लिए भारी संख्या में सुरक्षाबल तैनात किया गया था। इससे पहले पोस्टमार्टम के बाद जब उनका शव घर ले जाया गया, तो घर में कोहराम मच गया। बिलखती पत्नी ने कहा कि हत्यारों को फांसी की सजा दी जाए, नहीं तो ये लोग कई लोगों को मारेंगे। कन्हैया की हत्या कैसे और क्यों हुई? 10 दिन पहले नूपुर शर्मा के सम्पर्क में सोशल मीडिया पर पोस्ट डालने वाले कन्हैयालाल का तालिबानी तरीके से मर्डर कर दिया गया। गौस और रियाज मंगलवार को दिनदहाड़े उसकी दुकान में घुसे। तलवार से कई वार किए और उसका गला काट दिया। दुकान में इश्वर समेत दो और कर्मचारी मौजूद थे। पुलिस ने मंगलवार को दोनों आरोपियों गौस मोहम्मद और रियाज जब्बार को राजसमंद से अरेस्ट किया था। इनके अलावा 3 अन्य लोगों को भी पुलिस ने पकड़ा है। हत्याकांड की जांच अब एनआईए ने अपने हाथ में ले ली है और दोनों हत्यारों के खिलाफ अनलॉफुल एक्टविटी एक्ट समेत आईपीसी की कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। दोनों आरोपियों को मंगलवार शाम उदयपुर से सटे राजसमंद जिले के भीम इलाके से गिरफ्तार किया गया है।

'लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ रहा हूं राष्ट्रपति चुनाव'

नई दिल्ली: विपक्ष की ओर से राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्रीय वित्त और विदेश मंत्री रहे हैं। यशवंत सिन्हा भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे हैं और उनके बेटे जयंत सिन्हा भाजपा के सांसद तथा पिछली मोदी सरकार में राज्यमंत्री रहे हैं। इन सबसे बावजूद पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा कि वह देश में लोकतंत्र को बचाने के लिए चुनाव मैदान में उतरे हैं। जीवन में कठिन संघर्ष किया, कभी परवाह नहीं की: यह पूछने पर कि जब विपक्ष के कई बेटे नेताओं ने जब यह प्रस्ताव ठुकरा दिया, तो आपने यह हिम्मत कैसे दिखाई? पूर्व केंद्रीय मंत्री ने



बड़े सहज भाव से कहा कि मैंने बराबर जीवन में कठिन संघर्ष किया है। कभी यह चिंता नहीं की है कि स्थितियां मेरे अनुकूल हैं या नहीं। मेरी लड़ाई भारतीय लोकतंत्र की रक्षा के लिए है: अपने बेबाक जवाब के लिए मशहूर रहे यशवंत सिन्हा ने कहा कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़कर वह देश के लोकतंत्र की रक्षा करना चाहते हैं।

उदयपुर मर्डर से चुनौती बढ़ी; जवान डेढ़ गुना बढ़ाए, आसमान से हमला हुआ तो हवा में ही सफाया

अमरनाथ यात्रा में स्टिकी बम का खतरा

नई दिल्ली: 3,888 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बाबा अमरनाथ की यात्रा पर इस बार मिनटों में तबाही मचाने वाले स्टिकी बम का खतरा है। 43 दिन लंबी चलने वाली यह यात्रा दो साल बाद हो रही है। जम्मू-कश्मीर से धारा-370 के हटने के बाद भी यह पहली यात्रा है। कश्मीर के इंस्पेक्टर जनरल विजय कुमार ने धारक को कन्फर्म किया कि इस साल स्टिकी बम और ड्रोन अटैक दो बड़े खतरे हैं, लेकिन इन दोनों से बचने का पूरा प्लान भी तैयार है। ड्रोन का जवाब तो हवा में ही दिया जाएगा। मौके पर तैनात आर्मी अफसर ने ये



भी कहा कि उदयपुर की घटना के बाद चैलेंज बढ़ गया है, लेकिन अभी सब कुछ कंट्रोल में है। 30 जून से 11 अगस्त तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए अब तक 3 लाख से ज्यादा लोग रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। यात्रा दो साल बाद हो रही है, इसलिए

श्रद्धालुओं का आंकाड़ा पुराने रिकॉर्ड तोड़ते हुए 8 लाख तक पहुंच सकता है। पलहगाम से अमरनाथ तक यात्रियों को एक तरफ से करीब 46 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है। इसमें तीन रातें रास्ते में बितानी होती हैं। वहीं बालटाल वाले दूसरे रूट से बाबा बफरानी की गुफा तक की दूरी लगभग 14 किलोमीटर है। हालांकि इस रूट में बारिश और बर्फबारी का रिस्क होता है। खतरों से निपटने के लिए तैयारी क्या है: अमरनाथ यात्रा में पहली बार केंद्र की 350 कंपनियों तैनात की गई हैं।

रियाज जब्बार और गौस मोहम्मद नेपाल के रास्ते कराची गए, मौलाना से ट्रेनिंग ली

उदयपुर: तालिबानी मर्डर का सामने आया पाक कनेक्शन

जयपुर: उदयपुर में हुए तालिबानी मर्डर के तार पाकिस्तान से जुड़े रहे हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) ने 8 से 10 मोबाइल नंबर ट्रेस किए हैं। इनकी लोकेशन पाकिस्तान से लेकर भारत में आ रही है। इन्हीं नंबरों पर रियाज जब्बार और गौस मोहम्मद की लगातार बातचीत भी हो रही थी। इस इनपुट ने खुफिया तंत्र के कान खड़े कर दिए हैं। प्रदेश के गृह राज्यमंत्री राजेंद्र सिंह यादव ने भी इस मामले को लेकर खुलासा किया है कि दोनों पाकिस्तान और अरब



देशों के लोगों से कॉन्टैक्ट में थे। इनके मोबाइल में पाकिस्तान और

अरब देशों के नंबर मिले हैं। रियाज और गौस की पाकिस्तान के नंबरों पर खूब बातचीत होती थी। राज्यमंत्री ने इनके कराची में ट्रेनिंग लेने का भी दावा किया है। बताया गया कि दोनों ने 2014-15 में करीब 15 दिन की ट्रेनिंग ली थी। पाकिस्तान के आका के बुलावे पर दोनों वहां गए थे। फैला रहे थे नफरत की आग: मंगलवार को उदयपुर में कन्हैयालाल की हत्या के बाद राजस्थान पुलिस के साथ ही खुफिया एजेंसियों में खलबली मच गई थी। जिस अंदाज में कन्हैयालाल को मारा गया, वह

तालिबानी तरीका था। इसके बाद सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल कर आरोपियों ने अपने मसूबे साफ कर दिए। एनआईए की जांच में गौस और रियाज के पाकिस्तानी कनेक्शन के पुख्ता सबूत मिले हैं। इन दोनों ने कराची से लौटने के बाद उदयपुर में युवाओं को भड़काना शुरू कर दिया था। उनके मन में नफरत की आग को भड़का रहे थे। यह भी जानकारी सामने आई है कि दोनों दावत-ए-इस्लाम नाम के पाकिस्तानी संगठन से जुड़े हैं।

उपराष्ट्रपति पद के लिए 6 अगस्त को होगा मतदान

नई दिल्ली: चुनाव आयोग ने बुधवार को उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। एक से अधिक उम्मीदवार होने पर 6 अगस्त को मतदान होगा और उसी दिन नतीजे आयेगे। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त होने जा रहा है। आयोग ने इस संबंध में बुधवार को बैठक की। इस बैठक में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनूप चन्द्र पांडे शामिल थे। बैठक के बाद आयोग ने चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। उपराष्ट्रपति पद के लिए संसद के दोनों सदनों के सांसद वोट करते हैं।



कुल 788 सांसद उपराष्ट्रपति पद के लिए वोट करेंगे। इसमें राज्यसभा के 233, नामित सदस्य 12 और लोकसभा सदस्य 543 हैं। सभी की कीमत एक वोट होगी। लोकसभा महासचिव इस चुनाव में पीठासीन अधिकारी होंगे। सभी सांसदों को आयोग की ओर से मतपत्र और उस निशान के लिये पेन दिया जाएगा। मतदान संसद भवन में ही होगा।

बच्चों पेट खराब होने पर दिखाई देते हैं ये 5 संकेत, जानें बचाव के उपाय



बच्चों में खराब पेट के संकेत

खराब पेट के कारण आपके बच्चों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। हम सभी जानते हैं कि स्वस्थ पेट संपूर्ण स्वास्थ्य की कुंजी है। आपके शारीरिक, मानसिक, त्वचा और यहां तक कि बालों के स्वास्थ्य के लिए भी पेट का स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि बच्चे पाचन संबंधी समस्याओं का सामना बहुत अधिक करते हैं। दरअसल पेट को स्वस्थ रखने में पाचन तंत्र की अहम भूमिका होती है, लेकिन छोटे बच्चों का पाचन कमजोर होता है। जिससे उन्हें पाचन से जुड़ी समस्याएं अधिक होती हैं। मैटरनल चाइल्ड न्यूट्रिशनल रिमता कौर की मांमों तो खराब पेट आपके बच्चे की इम्यूनिटी को कमजोर बनाता है। क्योंकि 80व तक इम्यूनिटी बनाने का काम आपके पेट में होता है। इसलिए बच्चों के पेट को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है। बच्चों की गट हेल्थ खराब होने पर कई संकेत और लक्षण देखने को मिलते हैं। इस लेख में हम आपको बच्चों में खराब पेट के संकेत और बचाव के उपाय बता रहे हैं।

1. फाइबर रिच फूड्स खिलाना

अगर आप बच्चे को पेट संबंधी समस्याओं से बचना चाहते हैं, तो आपको उनके आहार में सबुत अनाज, दालें, नट्स, बीज, फल और सब्जियां शामिल करने की कोशिश करनी चाहिए। फाइबर पाचन को बेहतर बनाने में मदद करता है। जिससे पेट में गैस, ब्लोटिंग, कब्ज, उल्टी-दस्त, कब्ज जैसी समस्याएं नहीं होती हैं।

2. आहार में प्रोबायोटिक्स शामिल करें

बच्चों को प्रोबायोटिक्स खिलाना उनकी आंतों के लिए बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि यह आपके आंत में अच्छे बैक्टीरिया को बढ़ावा देते हैं। जिससे यह पाचन को बेहतर बनाने में मदद करते हैं। इसलिए बच्चों के आहार में दही, छाछ के साथ ही फर्मेंटेड फूड्स जैसे केफिर आदि को शामिल करने की कोशिश करें।

3. भोजन के दौरान छोटी-छोटी मील दें

कोशिश करें कि आप बच्चों को जब भोजन कराएं तो दिन में 3 बड़े भोजन की बजाए उन्हें थोड़ी-थोड़ी मात्रा में भोजन दें, लेकिन कई बार भोजन कराएं। इससे उनके पेट और पाचन तंत्र को रिफ्रेश करने में मदद मिलती है और पेट संबंधी समस्याएं नहीं होती हैं।

4. बच्चों को पर्याप्त पानी पिलाना

मजबूत और बेहतर पाचन के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी का सेवन बहुत जरूरी है। इसलिए बच्चों को पानी और तरल पदार्थों का अधिक सेवन कराएं। आप उन्हें ऐसे फूड्स भी दे सकते हैं जिनमें पानी की मात्रा भरपूर होती है। उन्हें नारियल पानी पिलाना, तरबूज, खरबूजा, खीरा आदि जैसे पानी से भरपूर फूड्स खिलाना।

5. फिजिकल एक्टिविटी भी है जरूरी है

बच्चों को पेट संबंधी समस्याओं से बचाने और पाचन को दुरुस्त रखने के लिए बच्चों को शारीरिक रूप से सक्रिय रखना बहुत जरूरी है। उन्हें बाहर खेलने और कुछ सिंपल एक्सरसाइज करने के लिए प्रोत्साहित करें।

खाद्य मुद्रास्फीति नहीं 'लालचस्फीति' से महंगाई

मुंबई के इंदिरा गांधी इंस्टिट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च (आईजीआईडीआर) की छात्र-पत्रिका के लिए साक्षात्कार में मुझसे पूछा गया कि खाद्य मुद्रास्फीति को नाथने हेतु क्या उपाय हो सकते हैं। यह प्रश्न कोई नया नहीं है, क्योंकि हर किसी के मन में यही सवाल होता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से लेकर किसी टीवी चैनल के वार्ता पैनलों पर या अखबारों में मुद्रास्फीति पर खबरें देखें तो यह ऊपर उठती खाद्य मुद्रास्फीति है, जिसे विकास-गाथा में खलनायक की तरह पेश किया जाता है।

हमारे दिमागों में यह भर दिया गया है, चूँकि भोजन एक मूल आवश्यकता है, इसलिए इसकी कीमतों में बढ़ोतरी को मैक्रो-इकोनॉमिक सूचकांक के 4 फीसदी अंतराल (दो फीसदी ऊपर या दो प्रतिशत नीचे) के अंदर बनाए रखना जरूरी है। इसलिए जब कभी नए फसल खरीद मूल्य घोषित किए जाते हैं, साल में दो मर्तबा यानी रबी और खरीफ की फसल के लिए, तब-तब मीडिया में बढ़ती खाद्य मुद्रास्फीति का हौवा उठ खड़ा होता है। इस साल भी, जब खरीफ फसलों का मूल्य घोषित हो रहा था, एक सवाल बार-बार टीवी चैनलों (और अखबारों में भी) चला हुआ कि क्या इससे खाद्य मुद्रास्फीति पैदा नहीं होगी? हालांकि, खरीफ की 14 में 11 जिन्सों के लिए मूल्य घोषित हुए, वे मुद्रास्फीति वाले मूल्य से भी कम थे, फिर भी फसल खरीद मूल्य में मामूली बढ़ोतरी को मुद्रास्फीति पर दबाव के लिए जिम्मेवार मानकर अंगुलियां उठाई जा रही थीं।

यह सर्वविदित है कि उपायोक्त मूल्य सूचकांक में खाद्य वस्तु वाला अवयव लगभग 45 प्रतिशत है। लेकिन कई बार हैरानी होती है कि मकान-चाहे अपना हो या किराए-वहां रहने के खर्च पर किसी परिवार की मासिक आय का एक बड़ा हिस्सा खप जाता है, इस तत्व को क्यों नहीं मुद्रास्फीति सूचकांक की गणना करते वक्त शामिल किया जाता। इसी तरह पर्यटन-तफरीह, धीरे-धीरे ऊपर उठती तेल कीमतें, हवाई, रेल एवं टैक्सी सेवा के गतिशील मूल्य, जिन पर होने वाला खर्च किसी औसत परिवार के रसोई-व्यय से कहीं अधिक होता है, उन्हें भी मुद्रास्फीति सूचकांक की गणना करते वक्त क्यों नहीं गिना जाता। कुछ दिन पहले, जिस रोज श्रीनगर से अधिकांश उड़ानें स्थगित कर दी गई थीं, जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने लगातार बढ़ते हवाई यात्रा किराए को खुली लूट बताया था। अधिकांश लोग मुम्बई-दिल्ली के बीच एकतरफा हवाई किराया यानी 25000 रुपये को अत्यधिक नाजायज बताते हैं। इसलिए, मुद्रास्फीति असल में कौन-सी चीज बनाती है, उसका पुनः निर्धारण होना चाहिए और महंगाई के लिए जिम्मेवार विभिन्न अवयवों के मुताबिक उनकी हिस्सेदारी तय की जाये।

यहां जो मैं कहना चाहता हूँ, वह यह है कि टैक्सी सेवा उपलब्ध करवाने



वाले मंच (ओला या उबर) सुबह के वक्त-यहां तक कि 6 बजे के ठीक-ठाक उजाले में भी- किराया बढ़ाकर लेते हैं, लेकिन वहीं जब टमाटर के दाम 20 से 40 रुपये हो जाएं तो आसमान टूट पड़ता है, जबकि टमाटर के बड़े दाम का भार भी किसी परिवार पर चीनी की एक किलोग्राम कीमत जितना भी नहीं पड़ता। भरे दिन में भी ओला-उबर कई बार 'सर्ज' लगा किराया वसूलते हैं, लेकिन गुस्सा सिर्फ टमाटर के दाम बढ़ने पर बनता है। तो इस तरह हमारे दिमागों को पट्टी पट्टा दी गई है। हमें यकीन दिलवाया जाता है कि मूल्य उत्पादन-आपूर्ति में फर्क आने से बढ़ेंगे लेकिन सामान्यतः हम लोग अहसास ही नहीं कर पाते कि एक तीसरा छिपा अवयव भी है हेइडरफेरी। ऐसे मौके भी हैं जब प्याज के उत्पादन में महज 4 प्रतिशत की कमी होने पर देश के कई हिस्सों में खुदरा मूल्य 600 गुणा से ज्यादा बढ़ा दिए गए।

इस बारे में तमिलनाडु में जैविक खेती करने वाले एमजे प्रभु की बात सुनें- 'मैं अपने बगीचे से प्रति नारियल 8 रुपये बेचता हूँ, बिचौलिया आगे इसे 28 रुपये में तो गली का रेहड़ी वाला या दुकानदार प्रति नारियल भाव 50 से 55 रुपये वसूलता है। यह आपूर्ति शृंखला चलाने वालों का लालच है, जिसकी वजह से नारियल का भाव खेत से उपभोक्ता के बीच 7 गुणा बढ़ जाता है। अतएव खाद्य-मुद्रास्फीति का ज्यादा संबंध खेत में लगी कीमत से न होकर बीच वालों की मुनाफाखोरी से है।'।

किसी सुपर मार्केट में जाएं और कीमतों का विश्लेषण करें, तो एक नया चलन बड़े पैकेटों पर साफ दिखाई देता है। सामान्यतः अर्थशास्त्र नियम कहता है कि बड़े पैमाने पर प्रसंस्करण कर बनाए खाद्य पदार्थों की कीमतें

सम्पादकीय

किताब की आब

माटी और मातृभाषा में रचे गये साहित्य से भी नई पीढ़ी रूबरू हो। इसकी पहल शिक्षकों, अभिभावकों व हमारे नीति-नियंत्रकों को करनी चाहिए। ऐसे में पढ़ने-लिखने के संस्कार विकसित करने की दिशा में हिमाचल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर की वह पहल प्रेरक है, जिसमें वे खुद स्कूलों में जाकर बच्चों को पाठ्यक्रम से अलग पुस्तकें भेंट करते हैं और उनमें पढ़ने-लिखने के संस्कार विकसित कर रहे हैं। इनमें वे पुस्तकें शामिल हैं जिनमें देश, समाज और संस्कृति के लिये महान योगदान देने वाले नायकों का जिक्र है। राज्यपाल ने केवल पुस्तकें देते हैं बल्कि खुद उनकी प्रतिक्रिया भी आमंत्रित करते हैं। एक छात्र ने उन्हें पत्र लिखकर बताया कि उसे नहीं मालूम था कि पाठ्यक्रम से इतर पुस्तकें भी उन्हें पढ़नी चाहिए। निस्संदेह, पुस्तकें विद्यार्थियों को दृष्टि को समृद्ध करती हैं। एक पुस्तक में कालखंड व जीवन के घनीभूत अनुभवों का समावेश होता है। पुस्तकें विद्यार्थियों में जहां पढ़ने के संस्कार विकसित करती हैं, वहीं इनसे भाषायी संस्कारों का भी विकास होता है। उनमें यह सोच विकसित करती हैं कि विषम परिस्थितियों में कैसा व्यवहार करना चाहिए।

जनता को ही नकारना होगा दल-बदलुओं को

देश के पक्ष-विपक्ष के नेताओं को आज ऐसी किसी समस्या की चिंता नहीं जैसी आमजन को है। आमजन महंगाई से त्रस्त है। दवाई और पढ़ाई सबको उपलब्ध नहीं, इससे वे पीड़ित हैं, पर यही पीड़ा माननीयों को नहीं सहनी पड़ती। एक बार विधायक या सांसद बन गए तो उनके सारे परिवार को चिकित्सा सुविधा देना सरकारों का मानो कर्तव्य ही बन जाता है। महंगाई भी नेताओं को तंग नहीं करती, क्योंकि वेतन और भत्ते इतनी मात्रा में मिल जाते हैं कि हर चीज उन्हें सस्ती लगती है।

देश के बहुत लोग रात को भूखे सोते हैं। फुटपाथ पर ही जन्म लेते और मर जाते हैं। बढ़ती जनसंख्या और उस पर कोई भी सरकारी नियंत्रण न होना गरीब की मुसीबतें बढ़ा रहा है। देश के नेताओं के सामने दो ही समस्याएं हैं। सत्तापक्ष सत्ता बनाए रखने के लिए तथा दूसरी पार्टियों से सत्ता छीनने के लिए लगातार प्रयास करता है और विपक्षी दल हाथों से निकली राजसत्ता पुनः प्राप्त करने के लिए किसी भी सीमा तक जाने को तैयार हो जाता है। नेताओं को तो बस सड़कों पर आकर नारे लगाने का कोई बहाना चाहिए। जनता की कठिनाइयों का कारण वे जनप्रतिनिधि हैं जो येन-केन प्रकारेण धनबल से, बाहुबल से, छल-धोखे से चुनाव तो जीत जाते हैं और उसके बाद वे ज्यादा सत्ता या धन पाने के लिए मार्केट में बिकने को पूरी तरह तैयार रहते हैं। आश्रय यह भी है कि जो लोग करोड़ों रुपये रिश्वत में देकर वोट खरीदते हैं उनके भी चुनावी खर्च विवरण को इस देश का चुनाव कमीशन स्वीकार कर लेता है।

इन दिनों पंजाब की भगवंत मान सरकार भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को नियंत्रित करने के लिए उन लोगों को कानून के घेरे में ले रही है जो कभी कानून के स्वामी थे, अधिकारी भी और विधायक, सांसद, मंत्री रहे लोग भी, पर सरकारों को उत्तर यह देना होगा कि भ्रष्टाचार में उनकी भी भूमिका अनदेखी क्यों होती है जो आज एक दल का डंडा और झंडा हाथ में उठाकर जनता से वोटों की भिक्षा मांगते हैं व कुछ दिन बाद वह झंडा फेंक कर किसी दूसरी पार्टी का चुनाव चिन्ह अपने गले में बड़ी शान से ओढ़ते हैं, उस पार्टी में सांसद चुटने की बात कहते हैं।

विडंबना है कि खरीद-फरोख्त के डर से विधायक कभी कर्नाटक के सुखद आवासा में भेजे गए, कभी राजस्थान में उनके लिए वातानुकूलित कक्ष आरक्षित हो गए। जो व्यक्ति संदिग्ध चरित्र का हो उसे तो कोई अपने यहां चपरासी भी नहीं

रखता, पर जिनका संदिग्ध व्यवहार है या जिनके बिकने की आशांका है उन्हें हवाई जहाजों में उड़कर ये सत्तापति सुरक्षित रखने के लिए ले जाते हैं तो क्या ऐसे अविश्वसनीय जनप्रतिनिधियों का कोई आत्मसम्मान शेष रह जाता है? आश्चर्य है कि जिनमें भेड़-बकरियों की तरह हवाई जहाजों में बंद कर किसी स्थान में रखा जाता है वे हंसते भी हैं, मुस्कुुरते भी हैं, मनोरंजक कार्यक्रमों का आनंद भी लेते हैं और मीडिया के सामने इस तरह प्रस्तुत किए जाते हैं जैसे ये लोकतंत्र की शान हों। आज लोकतंत्र की दुर्गाति और जनता की दयनीय स्थिति के जिम्मेवार यही जनप्रतिनिधि हैं जो धन के लिए या अधिक सत्ता पाने के लिए किसी भी मार्केट में बिकने को तैयार रहते हैं। इन दिनों पंजाब में कुछ पूर्व मंत्रियों और एक-दो वर्तमान मंत्रियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे। वे पकड़े भी गए, जेल में भी पहुंचे। यद्यपि कानूनी प्रक्रिया में उन्हें अपराधी या निर्दोष घोषित होने में बहुत समय लगेगा। प्रश्न है कि अगर कोई ठेकेदार से कमीशन लेने वाला या स्वास्थ्य विभाग के लिए खरीद-फरोख्त करने वाला भ्रष्ट माना जाता है तो जनता के वोट लेकर जनता को धोखा देने वाला क्या माना जाए? बंगाल के एक नेता को तो सांस चुटने की बीमारी हो गई। इतनी ज्यादा जितनी शायद कोरोना मरीज को भी नहीं होगी। जैसे ही उसने दल बदला उसका सांस सही चलने लगा।

चुनाव आयोग से आशा तो यह रखी जाती है कि जो चुनावी उम्मीदवार धनबल और बाहुबल का असीमित प्रयोग करते हैं, चुनाव आयोग की सारी संहिताओं की धज्जियां उड़ा देते हैं उन्हें चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित किया जाए। जो दल बदलें हैं उनकी सदस्यता भी समाप्त की जाए, पर शायद ये शक्तियां चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में नहीं। भारत सरकार को संसद में कानून बनाकर घोषित करना चाहिए कि जो दल बदलता है उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। जिस पार्टी का झंडा और डंडा ये दल बदल लुप्त रहे हैं उसकी ओर से पुनः चुनाव लड़ें, तब सदस्य बन सकते हैं। तो फिर जनता को आगे आना होगा। सार्वजनिक तौर से दल-बदलुओं को नकारें। उनका अपने क्षेत्र में प्रवेश बंद करें और मांग यह करें कि जो दंड धोखेबाज को मिलता है वही दंड उनको मिलना चाहिए जो एक पार्टी से चुनाव जीतकर जनता को विश्वास दिलाकर अपने स्वार्थों के लिए विश्वास तोड़ते हैं और यह आवाज उठे कि इनको माननीय क्यों कहा जाता है, जो जनता को अमाननीय हैं, वे माननीय कैसे?



इससे विद्यार्थी देशकाल की चुनौतियों से भी रूबरू होते हैं। उनकी सोच विकसित होती है और वे आदर्श नागरिक बनने की ओर अग्रसर होते हैं। स्कूल पाठ्यक्रम से उषजी एकरसता तोड़ने का काम भी पुस्तकें करती हैं। इसमें दो राय नहीं है कि हमारे मौजूदा समाज में शिक्षा के मायने बदल गये हैं। एक बेहतर नागरिक के निर्माण की जो भूमिका होती थी, उसकी जगह गलाकाट स्पर्धा और आर्थिक प्राथमिकताओं ने ले ली है। जीवन मूल्यों व आदर्शों का हमारे जीवन में तिरोहित होना कालांतर सामाजिक विद्रुपताओं को जन्म देता है। समाज में हिंसक व्यवहार और अपराधों का बढ़ना भी हमारे जीवन मूल्यों का पराभव ही है। निस्संदेह शिक्षा का लक्ष्य महज अंकों की होड़ ही नहीं है, बल्कि विद्यार्थी में मानवीय मूल्यों व संस्कारों का विकास भी है। देश में बढ़ते यौन और बाल अपराधों में वृद्धि चिंता का विषय है। निस्संदेह देशकाल-परिस्थिति किसी बालमन के भटकाव का प्राथमिक कारण हो सकता है लेकिन वह शिक्षा भी जरूरी है जो बच्चों में विवेक पैदा कर सके। जीवन व्यवहार के मूल्य हर युग में एक जैसे ही होते हैं।

